जीवन-कारोबारी सुगमता पर जोर

उम्मीदें

बजट-2022-23

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान ब्यूरो

अब तक 25 हजार अनुपालन बोझ कम किए

केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने रहन-सहन और कारोबार सुगम बनाने के लिए कई सुधारों को लागू कर अबतक 25000 से अधिक अनुपालन बोझ कम किए गए हैं। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री का जोर कारोबारी सुगमता बढ़ाने और कर अनुपालन का बोझ घटाने पर रहा है। इस दिशा में सरकार ने काफी तेजी से काम किया है। यही वजह है कि कोरोना संकट में भी हर माह लाखों की संख्या में नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कंपनियों और आम लोगों को होने वाली दिक्कतों की पहचान करने के लिए फिर से एक पहल शुरू की है। पिछले माह इन विषयों पर विचार-विमर्श कर मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आम लोगों को रोजमर्रा के जीवन में और कारोबार करते समय कई गैर-जरूरी अनुपालनों का सामना करना पड़ता है। इस बार के बजट में सरकार इन अनुपालनों का बोझ काफी हद तक दूर करने के लिए कदम उठा सकती है।

पिछले साल प्रधानमंत्री ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने और अनुपालन बोझ घटाने को लेकर विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों संग बैठकर कर उन्हें दिशा-निर्देश दिए थे। इस बार सरकार की तैयारी और बेहतर है।

केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों और राज्यों में सिंगल विंडो सिस्टम और विभागों के बीच एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।